

बीकाऊ पाडे एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य

25 नवंबर, 2003

[दोराईस्वामी राजू और अरिजीत पासायत, जेजे.]

दंड संहिता, 1860: धारा 149

सामान्य उद्देश्य-अभियोजन में-दायित्व के तहत-निर्णित किया गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बनाती थी-वहाँ एक सामान्य उद्देश्य होना चाहिए और व्यक्ति को उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित होना चाहिए--जहां सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होती है, वहां आरोपी उत्तरदायी नहीं है। धारा 149 की सहायता से दोषी ठहराया गया।

" सामान्य उद्देश्य "और" सामान्य आशय "-अंतर समझाया गया है।

आपराधिक मुकदमा,

अभिप्रेरण-प्रभाव की अनुपस्थिति-निर्णित किया। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित करता है तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

अभ्यास और प्रक्रिया:

तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष-हस्तक्षेप-निर्णित किया। यदि जब तक वहाँ कुछ प्रकट अवैधता या गंभीर या गंभीर अनियमितता जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, तो सर्वोच्च न्यायालय तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेगा-भारत का संविधान, अनुच्छेद 136

शब्द और वाक्यांश।

" समान उद्देश्य के अग्रसरण में "-का अर्थ-दंड संहिता, 1860 की धारा 149 के संदर्भ में।

अपीलार्थी-अभियुक्तों को विचारण अदालत ने दंड संहिता, 1860 की धारा 302 सपठित धारा 149 के तहत दोषी ठहराया था। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की। इसलिए अपील दायर की गई है।

अपीलार्थियों की ओर से बहस की गई, आई.पी.सी. की धारा 149 को लागू करने के लिए आवश्यक अवयव स्थापित नहीं किये गये थे।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया:

1. दंड संहिता, 1860 की धारा 149 का जोर सामान्य उद्देश्य पर है न कि सामान्य इरादे पर। गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बना सकती है जब तक कि धारा 141 में निर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों में से एक या अधिक से वह प्रेरित हुआ था। जहां गैर-कानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य सिद्ध नहीं होता है, वहां अभियुक्तों की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्धि नहीं की जा सकती। तय करने के लिए

महत्वपूर्ण सवाल यह है कि आया, सभा पाँच या अधिक व्यक्तियों की थी और आया, उन व्यक्तियों ने धारा 141 में वर्णित एक या अधिक सामान्य उद्देश्यों में रूचि थी। यह कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एक स्पष्ट कार्य साबित नहीं होता है, जिसके खिलाफ एक गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह एक सभा का सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे समझना चाहिए था कि सभा गैरकानूनी थी और धारा 141 के दायरे में आने वाले किसी भी कार्य को करने की संभावना थी। 'ऑब्जेक्ट' शब्द का अर्थ है डिजाइन का उद्देश्य और इसे 'सामान्य' बनाने के लिए, इसे सभी को साझा करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो सभा की रचना करते हैं, अर्थात्, वे सभी इसके बारे में जानते हों और इस पर सहमत हों। आपसी परामर्श के बाद स्पष्ट समझौते से एक सामान्य उद्देश्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से आवश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य तुरंत शामिल होकर सहमत हो सकते हैं। एक बार निर्माण हो गया तो यह जरूरी नहीं कि उसी रूप में जारी रहे। यह किसी भी स्तर पर संशोधित की जा सकती है, बदली जा सकती है अथवा छोड़ी जा सकती है। धारा 149 की अभिव्यक्ति "सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण" का सख्त अर्थ लिया जाना

चाहिए जो "सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए" के समकक्ष हो। इसका उद्देश्य की प्रकृति के अनुसार सामान्य उद्देश्य से तुरंत संबंध होना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय होना चाहिए और उद्देश्य सिर्फ एक निश्चित स्तर तक अस्तित्व में रहे, उसके बाद नहीं। गैर-कानूनी सभा के सदस्यों के उद्देश्य की समानता एक निश्चित बिंदु तक हो सकती है, उसके बाद उनके उद्देश्य और जानकारी सामान्य उद्देश्य के अनुक्रम में क्या किया जाना है, उसके संबंध में अलग-अलग हो सकती है। ना सिर्फ उसके आदेश पर जानकारी, लेकिन यह भी कि वह किस हद तक उद्देश्य के समुदाय को साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप आई.पी.सी. की धारा 149 का प्रभाव एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर अलग-अलग हो सकता है। [210-ई-एच; 211-ए-ई]

2. " सामान्य उद्देश्य "एक" सामान्य आशय "से अलग है क्योंकि इसके लिए हमले से पहले एक पूर्व मेल और वैचारिक एकता की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक का एक ही उद्देश्य है और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते हैं। एक सभा का "सामान्य उद्देश्य" इसे बनाने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना है। यह सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से एकत्र किया जा सकता है। गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए, गैरकानूनी सभा के प्रत्येक

सदस्य का आचरण, हमले से पहले और उसके समय और उसके बाद का आचरण, अपराध का उद्देश्य, ये कुछ प्रासंगिक विचार हैं। घटना के एक विशेष चरण में गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उसके पास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सभी मामलों में, एक गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ, इसे कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए या सफल होना चाहिए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा, जो इसे इकट्ठा करने के समय गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इरादा या उद्देश्य, जो एक सभा को गैर-कानूनी करने के लिए आवश्यक है, शुरुआत में ही अस्तित्व में आता है। गैरकानूनी इरादे बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। एक सभा, जो अपने प्रारंभ में ही या उसके बाद कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह तत्काल घटनास्थल पर घटना के दौरान विकसित हो सकता है। [211-एफ-एच; 212-ए-सी]

3. उद्देश्य कार्य है वह जिसके लिए सभा के सदस्य निर्धारित करते हैं या प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य समान है, तो ज्ञान जो उद्देश्य है, जिसका अनुसरण किया जा रहा है, सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे सामान्य रूप से इस बात पर

सहमत होते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाना है और अब यह सभा का सामान्य उद्देश्य है। मानव मन में उद्देश्य का मनोरंजन किया जाता है, और यह केवल एक मानसिक नजरिया है। कोई सीधा साक्ष्य उपलब्ध नहीं हो सकता और एक जैसा ईरादा व्यक्तियों के कृत्य और परिणाम से ही ज्ञात हो सकता है। हालांकि सामान्य उद्देश्य का कोई परिस्थितिजन्य निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, यह युक्तियुक्त तरीके से सभा की प्रकृति, हथियार और घटना के समय, उससे पूर्व और बाद के व्यवहार से एकत्रित किया जा सकता है। शब्द “जाना” जो धारा 149 के दूसरे भाग में काम में लिया गया है, उसका अर्थ संभावना से कुछ अधिक है और इसे जानना ही चाहिए था और इसे “जानना ही चाहिए था” के अर्थ में नहीं लिया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कोई अपराध कारित होता है, तो सामान्य तथा गैर कानूनी सभा के सदस्यों को ज्ञान होता है कि इस तरह का अपराध कारित होने वाला है। फिर भी यह विपरीत कथन को सच नहीं करता है, ऐसे मामले हो सकते हैं, जो धारा 149 के दूसरे भाग में आते हों, ना कि पहले भाग में। धारा 149 के दोनों भागों के अंतर को छोड़ा नहीं जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता है। प्रत्येक मामले में यह एक मुद्दा होगा जिसे निर्धारित किया जाना है कि क्या किया गया अपराध पहले भाग के भीतर आता है या यह एक ऐसा अपराध था जैसे कि सभा के सदस्य जानते थे कि सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किए जाने की संभावना है और दूसरे भाग के भीतर

आता है। हालाँकि, ऐसे मामले हो सकते हैं जो सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए गए पहले अपराधों के भीतर होंगे। आम तौर पर, यदि हमेशा नहीं, तो दूसरे में होगा, जैसे, ऐसे अपराध जिन्हें पक्षकार सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में किए जाने की संभावना के बारे में जानते थे। [212-ई-एच; 213-ए-सी]

चिक्कारंगे गौड़ा बनाम मैसूर राज्य, ए.आई.और. (1956)एससी 731, में भरोसा किया।

4.1. भले ही कथित रूप से उद्देश्य की अनुपस्थिति को स्वीकार किया जाता है, पर उसका कोई परिणाम नहीं होता है और यह महत्वहीन हो जाता है। जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित कर देता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तुरंत दर्ज की गई थी और जो भी विस्तार किया गया है वह वास्तव में बहुत मामूली प्रकृति का है। केवल प्रतीत होने वाली विसंगतियाँ, जो विरोधाभास या चूक नहीं हैं या तुच्छ प्रकृति की हैं, अभियोजन के मामले की बुनियाद को प्रभावित नहीं करती हैं। इस मामले में यही स्थिति है। चोटों की संख्या भले ही हमलावरों की संख्या के साथ सह-संबंधित न हो, कोई सार नहीं है। [213-डी-ई]

लीला राम बनाम हरियाणा राज्य, ए.आई.और. (1999) एससी 3717, पर भरोसा किया।

4.2. भले ही अनुसंधान करने में अनियमितताएं या अवैधताएं हों इसका कोई परिणाम नहीं है। [213-एफ]

राजस्थान राज्य बनाम किशोर, ए.ओई.ओर. (1996) एससी 3035 और कर्नाटक राज्य बनाम के. यारप्पा रेड्डी, ए.ओई.ओर. (2000) एससी 185, पर भरोसा किया।

5. साक्ष्य पर आधारित तथ्यों के समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। चाहे इस न्यायालय का साक्ष्य पर एक अलग दृष्टिकोण हो। यह न्यायालय आम तौर पर साक्ष्य के पुनर्मूल्यांकन या साक्ष्य की समीक्षा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि विचारण अदालत या उच्च न्यायालय कानून या प्रक्रिया की त्रुटि करते हुए जिन निष्कर्षों पर पहुंच गया है, वे विकृत हैं। यह न्यायालय विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय की राय पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने के लिए साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं कर सकता है। यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर, कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं। यह न्यायालय एक नियमित अपील न्यायालय नहीं है जिसमें आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को इसकी शुद्धता की जांच के लिए लाया जा सकता है। यह केवल दुर्लभ या असाधारण मामले में है जहां कुछ स्पष्ट अवैधता या गंभीर या गंभीर अनियमितता है जिसके

परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, उनमें यह न्यायालय तथ्यों के एेसे निष्कर्ष में हस्तक्षेप करेगा।[214-एफ-एच; 215-ए-बी]

दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन, [1975] चार एस.सी.सी. 469;
रमनिक लाल गोकलदास बनाम गुजरात राज्य [1976] 1 एस.सी.सी. 6;
एम. दलबीर कौर बनाम पंजाब राज्य, [1976] 4 एस.सी.सी. 158;
रमनभाई नारनभाई पटेल बनाम गुजरात राज्य, [2000] 1 एस.सी.सी.
358 और चंद्र बिहार गुआम बनाम बिहार राज्य, जे.टी. [2002] 4
एस.सी. 62, पर भरोसा किया।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील सं. 104-
106/2003

पटना उच्च न्यायालय क्रि.ए. (डीबी) संख्या 303, 352 और 364/
1987 में के निर्णय और आदेश दिनांक 3.9.2002 से।

पी.एस. मिश्रा, तथागत एच. वर्धन, अमितेश सी. मिश्रा, विष्णु शर्मा,
तरुण के. झा एवं सी. डी. सिंह अपीलार्थियों के लिए।

प्रत्यर्थियों की ओर से बी.बी. सिंह और कुमार राजेश सिंह।

न्यायालय का निर्णय अरिजीत पसायत, जे. द्वारा दिया गया था।

पंद्रह व्यक्तियों को कथित तौर पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 (संक्षेप
में औई.पी.सी.) की धारा 302 सपठित धारा 149, 148 के तहत दंडनीय
अपराध के अभियुक्त सं. 9 (वर्तमान अपीलों में अपीलार्थी सं. 5) को

अतिरिक्त रूप से शस्त्र अधिनियम, 1959 (संक्षेप में 'शस्त्र अधिनियम') की धारा 27 के तहत दंडनीय अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ा। अभियुक्त सं. 2 महेंद्र राय (वर्तमान में अपीलार्थी सं. 8) जिस पर आई.पी.सी. की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अलग से आरोप लगाया गया था, उसे उक्त आरोप से बरी कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद उपरोक्तानुसार उसे आई.पी.सी. की धारा 302 सपठित धारा 149 के अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। 15 अभियुक्तों में से दो को दोषमुक्त कर दिया गया और तीन की उच्च न्यायालय में अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई।

अभियोजन कथन जैसा कि मुकदमे के दौरान सामने आया और जिसने अभियोजन मामले की नींव रखी, अनिवार्य रूप से इस प्रकार है:

17.8.1983 को, एक सरजुग राय (जिसे इसके बाद 'मृतक' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने कथित रूप से आरोपी के हाथों अपनी जान गंवा दी। सरजुग राय के मारे जाने की घटना से लगभग 5-6 साल पहले पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन हुआ था। कमल राय उनका भतीजा था, जिसने अपने चाचा के खिलाफ गंभीर द्वेष से पोषित किया, जैसा कि उसके अनुसार पैतृक संपत्तियों का असमान विभाजन हुआ। कमल राय ने कहा कि उसका दृढ़ विश्वास था कि मृतक द्वारा विभाजन के बाद नए घर का निर्माण और ट्रैक्टर की खरीद उस नकदी से की गई थी, जिसे विभाजन के दौरान

विभाजित नहीं किया गया था। यद्यपि उद्देश्य तुच्छ और बासी भी प्रतीत होता है, लेकिन जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध है, उद्देश्य महत्वहीन हो जाता है। मृतक के पुत्र रामबाबू राय (पीडब्ल्यू-14) की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं मुकदमे में गवाहों द्वारा दिए गए कथन यह हैं कि 17.8.1983 को जब मृतक सुबह लगभग 8 बजे मंदिर के बगल के एक तालाब में पवित्र डुबकी लगाने के बाद मंदिर गया तो पकड़े हुए अपीलार्थीगण कमल राय के घर से मंदिर में आया, जिसके अनुसार कमल राय ने दूसरों को मृतक को समाप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए उसके सिर पर एक कठोर और कुंद पदार्थ से वार किया क्योंकि उसने पैतृक संपत्तियों को विभाजित करने में उसके साथ अन्याय किया था। मंदिर के पुजारी दुखा साह (पीडब्ल्यू-6) ने मृतक को बचाने के लिए मंदिर के उत्तरी द्वार को बंद कर दिया। हालाँकि, उसे बचाया नहीं जा सका-क्योंकि अपीलकर्ता देवशरण राय ने ताला तोड़ा और मृतक को बाहर खींच लिया, जिसके परिणाम कमल राय द्वारा किए गए प्रोत्साहन पर सभी ने उस पर घातक हथियारों से अंधाधुंध वार किए, जो वे अपने साथ लेकर आये थे।

जब शत्रुघन पाण्डे (पीडब्ल्यू-1), राम चन्द्र राउत (पीडब्ल्यू-2), नन्दलाल पाण्डे (पीडब्ल्यू-4) और सीतासरण राय (पीडब्ल्यू-5) मृतक के पुत्र (पीडब्ल्यू-14) का शोर सुनकर बचाने आये तो वे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सके। क्योंकि अभियुक्त-अपीलार्थी सत्य नारायण राय के फायर करने से डर गये। राम बाबू राय (पीडब्ल्यू-14) ने पुलिस को सूचित किया

जिसने गाँव बिशनपुर का दौरा किया और अपना बयान दर्ज कराया। जिसके आधार पर अनुसंधान शुरू किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (संक्षेप में संहिता) की धारा 161 के तहत गवाहों के बयान दर्ज करने के अलावा घटनास्थल का दौरा किया और कुछ आपत्तिजनक वस्तुओं को जब्त भी किया। अनुसंधान के समापन पर, उन्होंने सभी 15 अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अदालत के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिन पर अंततः मुकदमा चलाया गया। मुकदमे में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोषता और गलत निहितार्थ का कथन किया और उनके खिलाफ लगाये गये आरोपों के जवाब में 16 गवाहों का परीक्षण करवाया। अभियोजन पक्ष द्वारा जिन लोगों को परीक्षित करवाया उनमें बिशनपुर के ग्रामीण, कुछ बाहरी लोग थे, जो या तो मृतक के रिश्तेदार थे या दोनों पक्षों के बीच लंबित विवाद के समाधान के लिए पंचायत आयोजित करने के लिए गाँव गए थे। चिकित्सक और पुलिस अधिकारी भी थे।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अभियुक्त व्यक्तियों ने निर्दोष होने और दुश्मनी के कारण फंसाने का झूठा कथन किया है। तीन अभियुक्त व्यक्तियों ने घटना स्थल पर अपनी शारीरिक उपस्थिति को असंभव बताने के लिए अन्यत्र होने का कथन किया। अभियोजन पक्ष के गवाहों में से सात यानी पीडब्लू 2 से 5,6,10,14 को चश्मदीद गवाह बताया गया था। अभिलेख पर साक्ष्य पर विचार करने पर, तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,

सीतामढी ने 13 अभियुक्त व्यक्तियों को दोषी ठहराया, दो को दोषमुक्त कर दिया। तीन जिनकी उच्च न्यायालय के समक्ष अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, उनके संबंध में अपीलों को समाप्त कर दिया गया। दोषी ठहराए गए आरोपी ने तीन अलग-अलग अपीलें उच्च न्यायालय के समक्ष कीं। जिनका विवादित निर्णय द्वारा निपटारा किया।

अपीलों के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थियों को आई.पी.सी. की धारा 149 को लागू करके दोषी ठहराया गया है। उक्त प्रावधान को लागू करने के लिए आवश्यक सामग्री सिद्ध नहीं है। दो अभियुक्त व्यक्तियों के संबंध में अन्यत्र होने का कथन स्वीकार कर लिया गया है। हालाँकि, अपीलार्थी महेंद्र राय बेहतर स्थिति में थे। फिर भी उनके अन्यत्र होने के कथन को गलत आधार पर खारिज कर दिया गया है। सबूत था और एक गवाह उसके अन्यत्र होने के समर्थन में प्रस्तुत किया गया।

जिसे बिना किसी आधार के खारिज कर दिया गया है। हालाँकि बड़ी संख्या में चोटें आई हैं, लेकिन आरोपी देव शरण राय (ए-1), कमल राय (ए-7) और सत्य नारायण राय (ए-9) को छोड़कर किसी विशेष आरोपी को विशेष भीड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। अभियुक्त कमल राय की मृत्यु हो चुकी है और बांकी दो इन अपीलों में क्रमशः 3 और 5 अपीलार्थी हैं। जिस उद्देश्य को अपराध की नींव के रूप में इंगित करने की

मांग की गई थी, वह बहुत कम है और वास्तव में देव नारायण राय (पीडब्लू-11), जो एक चश्मदीद गवाह नहीं हैं और जिन्होंने कमल राय के उद्देश्य के बारे में बात की है, उन्हें विचारण अदालत और उच्च न्यायालय दोनों ने अस्वीकार कर दिया है। गवाह निकटता से संबंधित हैं और वास्तव में पीडब्लू-11 को अविश्वसनीय के रूप में खारिज कर दिया गया है। जाँच निष्पक्षता से अधिक थी और नीचे के न्यायालयों को इस पर ध्यान देना चाहिए था। भीड़ में पहचान बेहद असंभव है। जब अन्यत्र होने की याचिका को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह स्पष्ट रूप से गलत फंसाने की सीमा और उसके लिए तरीके को इंगित करता है। अभियुक्तों में से एक रवीन्द्र पांडे घटना के समय एक बच्चा था। हालाँकि उसे बाल अधिनियम के तहत अलग से निपटा जाना चाहिए था और ऐसा नहीं करने पर उसकी दोषसिद्धि दूषित हो जाती है। अभियोजन पक्ष द्वारा वर्णित उत्पत्ति अत्यधिक असंभव है। यह विश्वास करने योग्य नहीं है कि मृतक एक ऐसे मंदिर में पूजा करने जा रहा था, जो प्रथम दृष्टया बिना किसी देवता के प्रतीत होता है। घटना के स्थान को इस तरह से चुना गया है जिससे पुजारी दुख साह (पीडब्लू-6) जैसे कुछ व्यक्तियों के साक्ष्य को कुछ विश्वास मिलेगा। अभियोजन पक्ष का सबूत यह है कि सभी आरोपी व्यक्ति आरोपी कमल राय के घर से आए थे। जिस स्थान पर पीडब्लू-6 ने उन्हें देखने का दावा किया है, वहां से दृश्यता लगभग असंभव है। यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि कमल राय ने दूसरों को बताया है कि उन्होंने क्या करने

का प्रस्ताव रखा था, या आम उद्देश्य साझा किया गया था। दूसरी ओर, भले ही यह समान या सामान्य इरादे का मामला था, अधिक से अधिक, अभियोजन पक्ष आई.पी.सी. की धारा 34 को लागू कर सकता था, जिसके लिए कोई आरोप नहीं था और आई.पी.सी. की धारा 34 को लागू करने के लिए भागीदारी आवश्यक है। सभी अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ बहुत ही सामान्य और दोहराए जाने वाले प्रकृति के आरोप लगाए गए हैं। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि सत्य नारायण राय के पास देसी बंदूक थी और इसलिए शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत दोषसिद्धि कायम रखने योग्य नहीं है।

जवाब में, राज्य के विद्वान वकील श्री बी.बी. सिंह ने प्रस्तुत किया कि सामान्य उद्देश्य धारा 149 आई.पी.सी. के तहत स्पष्ट रूप से सामने लाया गया है। निर्विवाद प्रमाण यह है कि घातक हथियारों से लैस सभी आरोपी व्यक्ति एक समूह में गाँव के बाहर से आए थे। मृतक को पहले घसीटा गया और फिर अभियुक्त कमल राय द्वारा

लाठी का वार किया। जो एक घातक था और जब उसका बेटा (पीडब्लू-14) उसे बचाना चाहता था तो दूसरों को बचाने के लिए उसके पास आने से रोकने के लिए गोली चला दी गई थी। धारा 149 को आकर्षित करने के लिए सबूत पर्याप्त से अधिक थे। जहाँ तक गवाहों की कथित रुचि का संबंध है, यह सामान्य कानून है कि यदि सावधानीपूर्वक

विश्लेषण और जांच के बाद, साक्ष्य विश्वसनीय पाया जाता है, तो दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। इसके अलावा, ऐसे गवाह थे जो किसी भी तरह से संबंधित नहीं थे। जहाँ तक प्रत्यक्षीकरण के प्रश्न का संबंध है, जब संबंधित अभियुक्त की उपस्थिति संतोषजनक रूप से स्थापित हो जाती है, तो न्यायालय जवाबी साक्ष्य पर विश्वास करने में तब तक विलंब करेगा जब तक कि यह ऐसी गुणवत्ता का न हो जो न्यायालय के मन में एक उचित संदेह पैदा करे कि अभियोजन पक्ष का सबूत ठोस नहीं था। विचारण अदालत और उच्च न्यायालय ने अन्यत्र होने की याचिका का विस्तार से विश्लेषण किया है और रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों को देखते हुए इसे खारिज कर दिया है। जहाँ तक अभियुक्त रवीन्द्र पांडे के नाबालिग होने के दावे का संबंध है, निचली अदालत द्वारा पारित दिनांक 27.07.1984 के आदेश से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि उसकी याचिका को खारिज कर दिया था। वास्तव में स्कूल के अभिलेखों ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया कि घटना की तारीख को उनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक थी। पिता ने यह कहने के लिए अप्रत्यक्ष उद्देश्य से एक हलफनामा दायर किया कि स्कूल रजिस्टर में गलत दर्ज थी। जाहिरा तौर पर, इस तरह की याचिका स्वीकार्य नहीं है और 27.7.1984 दिनांक आदेश मुकदमे के पूरा होने से बहुत पहले पारित किया गया था और उस पर हमला नहीं किया गया है जो अंतिम हो गया है। इसलिए, न तो विचारण अदालत ने और न ही उच्च न्यायालय ने इस

याचिका पर विचार किया है जो कि उक्त अदालतों के समक्ष भी नहीं उठाई गई है।

अभियुक्त की कथित आयु के आधार पर अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर पहले विचार करने की आवश्यकता है। अभियुक्त की आयु से संबंधित प्रश्न - मुकदमे के दौरान और अपील में, निचली अदालतों के समक्ष कभी नहीं उठाया गया। जिसमें निर्णय की आवश्यकता होती। वास्तव में, किशोर अधिनियम जिस पर अपीलार्थी भरोसा करते हैं, घटना के समय अस्तित्व में नहीं था। इसके अलावा मुकदमे के दौरान या उच्च न्यायालय के समक्ष किसी भी समय यह सवाल नहीं उठाया गया था। अभियुक्त की आयु निर्धारित करने की आवश्यकता तब उत्पन्न होती है जब अभियुक्त याचिका दायर करता है और न्यायालय संदेह को स्वीकार करता है। यहाँ, जब अभियुक्त द्वारा दावा किया गया कि वह एक बच्चा था, तो याचिका पर विचार किया गया और निर्णय दिया गया कि वह बच्चा नहीं था। उस आदेश के बिना किसी चुनौती के अंतिमता प्राप्त कर ली है। स्पष्ट रूप से यह दलील कि स्कूल रजिस्टर गलत था, पिता के स्व-सेवारत हलफनामे को स्वीकार करके स्वीकार नहीं की जा सकती है। किसी भी सूरत में, इस मुद्दे पर विचारण अदालत या उच्च न्यायालय के समक्ष कोई दलील पेश नहीं की गई थी और उसके विवादित तथ्यात्मक प्रश्न, जो पहले के आदेश को देखते हुए अंतिम रूप भी प्राप्त कर चुका है, उसे उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तुरंत दर्ज की गई थी। पुलिस थाना घटना के स्थान से 4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। यह घटना सुबह करीब आठ बजे हुई। एफ.आई.और. लगभग तुरंत सुबह 10.00 पर दर्ज की गई। जाँच अधिकारी सुबह 11.00 बजे घटना स्थल पर पहुंचा और शाम 4 बजे पोस्टमार्टम किया गया। अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि चश्मदीद गवाहों से दोपहर 2 बजे से पूछताछ की गई थी।

कुछ अभियुक्त व्यक्तियों को बरी करने से अन्य अपीलकर्ताओं को राहत नहीं मिलेगी जिनके संबंध में उच्च न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार किया है और उन्हें दोषी पाया। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, पीडब्लू-1 का मृतक के साथ कोई संबंध नहीं है और परीक्षा में मुख्य रूप से उसके दावे को चुनौती नहीं दी गई है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि घटना के स्थान और घटना के तरीके के संबंध में विभिन्न गवाहों की प्रतिपरीक्षा में कुछ भी सामने नहीं आया है। यह स्थिति होने के कारण की गई दोषसिद्धियों को गलत नहीं ठहराया जा सकता है।

हम आई.पी.सी. की धारा 149 को लागू करने के प्रश्न पर विचार करेंगे, जिस पर जोरदार बहस की गई है।

प्रत्यर्थियों द्वारा जिस बहस पर जोर दिया गया था, वह इस सवाल से संबंधित है कि क्या आई.पी.सी. की धारा 149 प्रलक्षित दायित्व को बांधने

के लिए लागू है। जो इसके प्रचलन के लिए अनिवार्य है। साझा उद्देश्य पर जोर दिया जाता है न कि साझा इरादे पर। गैरकानूनी सभा में केवल उपस्थिति किसी व्यक्ति को उत्तरदायी नहीं बना सकती है, जब तक कि वहां एक सामान्य उद्देश्य हो और वह उस सामान्य उद्देश्य से प्रेरित न हो और वह उद्देश्य धारा 141 में उल्लिखित उद्देश्यों में से एक हो। जहाँ गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य साबित नहीं होता है, वहाँ अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 149 की मदद से दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। यह निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सभा में पाँच या अधिक व्यक्ति शामिल थे और क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 में निर्दिष्ट सामान्य उद्देश्यों में से एक या अधिक का मनोरंजन किया था। यह कानून के एक सामान्य प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ एक स्पष्ट कार्य साबित नहीं होता है, जिस पर गैरकानूनी सभा का सदस्य होने का आरोप है, यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सभा का एक सदस्य है। केवल एक चीज की आवश्यकता है कि उसे समझना चाहिए था, कि सभा गैरकानूनी थी और किसी भी कार्य को करने की संभावना थी, जो धारा 141 के दायरे में आती है। 'ऑब्जेक्ट' शब्द का अर्थ है उद्देश्य या डिजाइन और इसे 'सामान्य' बनाने के लिए, सभी द्वारा साझा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उद्देश्य उन व्यक्तियों के लिए सामान्य होना चाहिए, जो सभा की रचना करते हैं, अर्थात्, उन सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए और इस पर सहमति दें। आपसी

परामर्श के बाद स्पष्ट समझौते से एक सामान्य उद्देश्य का निर्माण किया जा सकता है, लेकिन यह किसी भी तरह से अनावश्यक नहीं है। इसका गठन किसी भी स्तर पर सभा के सभी या कुछ सदस्यों द्वारा किया जा सकता है और अन्य सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं और इसे अपना सकते हैं। एक बार बनने के बाद इसी रूप को, जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी भी स्तर पर संशोधित या परिवर्तित किया जा सकता है या त्याग दिया जा सकता है। धारा 149 की अभिव्यक्ति 'सामान्य उद्देश्य' के अग्रसरण का सख्त अर्थ लिया जाना चाहिए। जो 'सामान्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए' के समकक्ष हो। इसे उद्देश्य की प्रकृति के आधार पर तुरंत सामान्य उद्देश्य से जोड़ा जाना चाहिए। उद्देश्य का समुदाय होना चाहिए और उद्देश्य केवल एक विशेष चरण तक मौजूद हो सकती है, और उसके बाद नहीं। एक गैरकानूनी सभा के सदस्यों के पास एक निश्चित बिंदु तक उद्देश्य का समुदाय हो सकता है, जिसके आगे वे अपने उद्देश्यों और ज्ञान में भिन्न हो सकते हैं, जो प्रत्येक सदस्य के पास है कि क्या किया जा सकता है। उनके सामान्य उद्देश्य का अग्रसरण न केवल उसके आदेश पर दी गई जानकारी के अनुसार भिन्न हो सकता है, बल्कि उस सीमा के अनुसार भी भिन्न हो सकता है जिस तक वह उद्देश्य के समुदाय को साझा करता है, और इसके परिणामस्वरूप धारा 149, आई.पी.सी. का प्रभाव एक ही सभा के विभिन्न सदस्यों पर भिन्न हो सकता है।

"सामान्य उद्देश्य" एक "सामान्य आशय" से अलग है, क्योंकि इसके लिए हमले से पहले एक पूर्व मेल और वैचारिक एकता की आवश्यकता नहीं होती है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक का एक ही उद्देश्य है और उनकी संख्या पाँच या उससे अधिक है और वे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक सभा के रूप में कार्य करते हैं। एक सभा का "सामान्य उद्देश्य" इसे बनाने वाले सदस्यों के कार्यों और भाषा से और आसपास की सभी परिस्थितियों पर विचार करके निर्धारित किया जाना है। यह सभा के सदस्यों द्वारा अपनाए गए आचरण से एकत्र किया जा सकता है। गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य के निर्धारण के लिए, गैरकानूनी सभा के प्रत्येक सदस्य का आचरण, हमले से पहले और उसके समय और उसके बाद का आचरण, अपराध का उद्देश्य, ये कुछ प्रासंगिक विचार हैं। घटना के एक विशेष चरण में गैरकानूनी सभा का सामान्य उद्देश्य क्या है, यह अनिवार्य रूप से सभा की प्रकृति, सदस्यों द्वारा उठाए गए हथियारों और घटना स्थल पर या उसके पास सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जाने वाला तथ्य का प्रश्न है। कानून के तहत यह आवश्यक नहीं है कि गैरकानूनी सभा के सभी मामलों में, एक गैरकानूनी सामान्य उद्देश्य के साथ, इसे कार्रवाई में परिवर्तित किया जाना चाहिए या सफल होना चाहिए। धारा 141 के स्पष्टीकरण के तहत, एक सभा, जो इसे इकट्ठा करने के समय गैरकानूनी नहीं थी, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। यह आवश्यक नहीं है कि इरादा या उद्देश्य, जो एक सभा को गैर-कानूनी करने के लिए

अवश्यक है, शुरुआत में ही अस्तित्व में आता है। गैरकानूनी इरादे बनाने का समय महत्वपूर्ण नहीं है। एक सभा, जो अपने प्रारंभ में ही या उसके बाद कुछ समय के लिए भी वैध है, बाद में गैरकानूनी हो सकती है। दूसरे शब्दों में, यह तत्काल घटनास्थल पर घटना के दौरान विकसित हो सकता है।

आई.पी.सी. की धारा 149 के दो भाग हैं। धारा के पहले भाग का अर्थ है कि सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में किया जाने वाला अपराध वह होना चाहिए जो सामान्य उद्देश्य को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो। अपराध पहले भाग के भीतर आ सके इसके लिए, अपराध को तुरंत उस गैरकानूनी सभा के सामान्य उद्देश्य से संबंधित होना चाहिए, जिसका आरोपी सदस्य था। भले ही किया गया अपराध सामान्य उद्देश्य के प्रत्यक्ष अनुसरण में नहीं है तो भी यदि यह अभिनिर्धारित किया जा सकता है कि अपराध ऐसा था जैसा कि सदस्यों को पता था कि किए जाने की संभावना थी, तो यह धारा 141 के तहत आ सकता है और यही धारा के दूसरे भाग में अपेक्षित है। जिस कार्य के लिए सभा के सदस्य निर्धारित करते हैं या जिसे प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, वही उद्देश्य है। यदि सभी सदस्यों द्वारा वांछित उद्देश्य समान है, तो जिस उद्देश्य का अनुसरण किया जा रहा है, वह ज्ञान सभी सदस्यों द्वारा साझा किया जाता है और वे सामान्य रूप से इस बात पर सहमत होते हैं कि इसे कैसे प्राप्त किया जाना है, यही सभा का सामान्य उद्देश्य है। मानव मन में उद्देश्य का मनोरंजन किया जाता है और

यह केवल एक मानसिक दृष्टिकोण होने के कारण, कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं हो सकता है और एक जैसा इरादा, आम तौर पर उस कार्य से एकत्र किया जाना चाहिए जो व्यक्ति करता है और उसका परिणाम होता है। हालांकि सामान्य उद्देश्य का कोई परिस्थितिजन्य निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता, यह युक्तियुक्त तरीके से सभा की प्रकृति, हथियार और घटना के समय, उससे पूर्व और बाद के व्यवहार से एकत्रित किया जा सकता है। शब्द “जाना” जो धारा 149 के दूसरे भाग में काम में लिया गया है, उसका अर्थ संभावना से कुछ अधिक है और इसे जानना ही चाहिए था और इसे “जानना ही चाहिए था” के अर्थ में नहीं लिया जा सकता। सकारात्मक ज्ञान आवश्यक है। जब सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कोई अपराध कारित होता है, तो सामान्य तथा गैर कानूनी सभा के सदस्यों को ज्ञान होता है कि इस तरह का अपराध कारित होने वाला है। फिर भी यह विपरीत कथन को सच नहीं करता है, ऐसे मामले हो सकते हैं, जो धारा 149 के दूसरे भाग में आते हों, ना कि पहले भाग में। धारा 149 के दोनों भागों के अंतर को छोड़ा नहीं जा सकता और ना ही मिटाया जा सकता है। इसलिए, धारा 149 को सही ढंग से लागू किया गया है, जब प्रत्यक्षदर्शी द्वारा उजागर की गयी तथ्यात्मक स्थिति पर विचार किया जाता है। भले ही कथित रूप से उद्देश्य की अनुपस्थिति को स्वीकार किया जाता है। जिसका कोई परिणाम नहीं है, जब प्रत्यक्ष साक्ष्य अपराध को स्थापित करता है तो यह महत्वहीन हो जाता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग तुरंत

दर्ज की गई थी और जो भी विस्तार किया गया है वह वास्तव में बहुत मामूली प्रकृति का है। केवल प्रतीत होने वाली विसंगतियाँ जो विरोधाभास या चूक नहीं हैं या तुच्छ प्रकृति की हैं, अभियोजन मामले की बुनियाद को प्रभावित नहीं करती हैं। इस मामले में यही स्थिति है। चोटों की संख्या भले ही हमलावरों की संख्या के साथ सह-संबंधित न हो, कोई सार नहीं है। [लीला राम (मृतक) के माध्यम से दुली चंद बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, ए.ओई.और. (1999) एससी 3717 को देखें]

इसी तरह, भले ही अनुसंधान करने में अनियमितताएं या अवैधताएं हों इसका कोई परिणाम नहीं है। [राजस्थान राज्य बनाम किशोर, ए.ओई.और (1996) एस.सी. 3035 और कर्नाटक राज्य बनाम के. यारप्पा रेड्डी, ए.ओई.और. (2000) एससी 185 देखें]

अन्यत्र होने की याचिका को खारिज करने के लिए विचारण अदालत और उच्च न्यायालय ने ठोस कारण दिए हैं। जहां तक अभियुक्त महेंद्र राय का संबंध है, केवल इसलिए कि दो अभियुक्तों के संबंध में याचिका स्वीकार की गई थी, यह अन्यत्र होने की याचिका को स्वीकार करने का आधार नहीं हो सकता है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि घटना की तारीख 17.8.1983 है और माना जाता है कि आरोपी महेंद्र राय ने 10.8.1983 से घटना की तारीख तक सेवा की है। विचारण न्यायालय ने देखा कि उस तारीख को यह दिखाने के लिए कोई भी सामग्री नहीं थी कि घटना के

समय वह पूरे समय स्कूल में मौजूद था और यहां तक कि नियुक्ति दिखाने वाला कोई नियुक्ति पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया था। यह प्रदर्शित प्रमाण पत्र से भी स्पष्ट है। प्रमाण पत्र इस आशय का था कि वह नियमित रूप से 10.8.1983 से 17.8.1983 तक की अवधि के लिए एक गार्ड के रूप में ड्यूटी पर था। यह अकल्पनीय है कि एक व्यक्ति को एक सप्ताह के लिए नियमित रूप से नियुक्त किया गया था। यह अन्यत्र होने की याचिका को अस्वीकार करने के लिए एक अतिरिक्त आधार है। उपस्थिति रजिस्टर पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर भी स्वीकार्य नहीं पाए गए।

केवल इसलिए कि दो व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया गया है, यह लाभ दूसरों को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि प्रत्यक्ष साक्ष्य से उनकी अपराध में उपस्थिति और भागीदारी स्थापित है। हालांकि यह दावा किया गया था कि वहाँ "जैसा कि चश्मदीद गवाहों द्वारा गवाही दी गई थी, ताला तोड़ने के संबंध में कोई सबूत नहीं था, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जांच अधिकारी के वस्तुनिष्ठ निष्कर्ष स्पष्ट रूप से नेतृत्व करते हैं ऐसी याचिका की स्वीकार्यता के लिए। टूटा हुआ ताला जब्त कर लिया गया और एक्जीबी-1 के रूप में प्रदर्शित किया गया। जाँच अधिकारी द्वारा दरवाजे पर हिंसा के निशान स्पष्ट रूप से देखे गए और नोट किए गए।

यह कानून में एक स्थापित स्थिति है कि जब तक यह नहीं दिखाया जाता है कि निष्कर्ष विकृत हैं, तब तक साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है।

हम यह पता लगाने के लिए पूरे अभियोजन मामले की फिर से जांच करने के लिए इच्छुक नहीं हैं कि क्या घटना इसी तरीके से हुई थी, जैसा अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया। हमें किसी भी चश्मदीद गवाह पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिलता है। विचारण न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उनके बयानों की आलोचनात्मक जांच के बाद सही निष्कर्ष निकाला है कि सभी गवाह विश्वसनीय हैं और यह इन अपीलों के सभी अपीलार्थी घटना के समय उपस्थित थे। केवल इसलिए कि गवाह मृतक के रिश्तेदार थे, उनकी गवाही को अस्वीकार करने का आधार नहीं है। मामले की परिस्थितियों में, उपरोक्त गवाह प्राकृतिक गवाह प्रतीत होते हैं, जिनका घटना स्थल पर उपस्थित होना अपेक्षित था। इस न्यायालय द्वारा बार-बार यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साक्ष्य के शुद्ध मूल्यांकन के आधार पर तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा, भले ही इस न्यायालय को साक्ष्य पर अलग दृष्टिकोण अपनाना हो। न्यायालय आम तौर पर पुनर्मूल्यांकन या साक्ष्य की समीक्षा में प्रवेश नहीं करेगा जब तक कि विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय को विधि या प्रक्रिया की त्रुटि करते हुए दिखाया गया है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे विकृत हैं। यह न्यायालय विचारण न्यायालय या उच्च न्यायालय के

स्थान पर अपनी राय प्रतिस्थापित करने के लिए साक्ष्य की विश्वसनीयता में प्रवेश नहीं कर सकता है।

यह न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है जहां सिद्ध तथ्यों पर, कानून के गलत निष्कर्ष निकाले गए हैं। इस बात पर जोर दिए जाने की आवश्यकता है कि यह न्यायालय एक नियमित अपील न्यायालय नहीं है, जिसमें आपराधिक मामले में उच्च न्यायालय के प्रत्येक निर्णय को इसकी शुद्धता की जांच के लिए लाया जा सकता है। यह केवल दुर्लभ या असाधारण मामला जहां कुछ स्पष्ट अवैधता या गंभीर या गंभीर अनियमितता है जिसके परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होती है, तथ्यों के ऐसे निष्कर्षों में हस्तक्षेप करेगा। इस संबंध में, दुली चंद बनाम दिल्ली प्रशासन, [1975] 4 एस.सी.सी. 469; रमनिक लाल गोकलदास और अन्य बनाम गुजरात राज्य, [1976] 1 एस.सी.सी. 6); एम. दलबीर कौर और अन्य बनाम पंजाब राज्य, [1976] 4 एस.सी.सी. 158; रमनभाई नारनभाई पटेल और अन्य बनाम गुजरात राज्य, [2000] 1 एस.सी.सी. 358 और चंद्र बिहारी गौतम और अन्य बनाम बिहार राज्य, जे.टी. (2002) 4 एससी 62 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय के निर्णयों का संदर्भ दिया जा सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि ऐसा कोई मामला है जिसमें किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर हस्तक्षेप की आवश्यकता है। अपीलें बिना किसी योग्यता के हैं और खारिज किए जाने के योग्य हैं, जिसका हम निर्देश देते हैं।

यह अनुवाद और्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी प्रशान्त चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा ।